Statement I

Extent of damages due to drought during post-monsoon period of 1986 (*as reported by States/UTs*) (*Provisional*)

	State	Districts affected	Cropped area affected (lakh ha.)	Population affected (in lakhs)	Cattle affected (in lakhs)
1.	Assam	16	5·58	20·00	10·99
2.	Manipur	8	1·88	9·92	NR
3.	Haryana	12	9·30	37·00	30.80
4.	Tamil Nadu	18	1·36	232·95	NR
5.	Pondicherry	2	0·04	0·77	0.04
6.	Uttar Pradesh	53	72.15	600.00	320.16
7.	Tripura	3	0·37	1·150 (Esttd.)	NR
8.	Andhra Pradesh	12	10.38	31·27 Small & marginal farmers)	—
		124	101·06	933·41	361·9

मध्य प्रदेश की केन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना

528. **श्री अजीत जोगी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश की केन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना काफी लम्बे अरसे से लंबित है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी स्वीकृति में क्या अड़चने हैं और उन अड़चनों को दूर करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ग) इस परियोजना को कब तक स्वीकृति दे दिये जाने की आशा है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) केन बहुउद्देशीय परियोजना जिस पर 202 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है, केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी, आर्थिक स्वीकृति हेतु 1982 में प्राप्त हुई थी । केन्द्रीय जल आयोग ने परियोजना की जांच कर ली है तथा विभिन्न पहलुओं पर राज्य सरकार को स्पष्टीकरण भेजने हेतु अपनी टिप्पणियां भेज दी हैं । बांध स्थल पर जल की उपलब्धता तथा उसके उपयोग के बारे में मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच कुछ मतभेद हैं । दोनों राज्य सरकारों के बीच इन मामलों को हल करने में केन्द्रीय जल आयोग उनकी सहायता करता आ रहा है । बांध स्थल पर विश्वसनीय जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारें और जल विज्ञान सम्बन्धी आंकड़े एकत्र कर रही हैं ।